ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती. राज कुमार और अन्य

14 नवम्बर 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पटना, जे.जे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

धारा 147- मुआवजे का निर्णय- उच्च न्यायालय ने 1.25 लाख रुपये का अनुदान पारित करते हुए, माना कि बीमाकर्ता का दायित्व 50,000 रुपये तक सीमित है। हालाँकि, बीमाकर्ता दावेदारों को पूरी राशि का भुगतान करेगा और बीमाकर्ता से 50,000, रुपये से अधिक की राशि वसूल करेगा। - अपील पर, बीमाकर्ता का दायित्व 50,000 रुपये तक सीमित है - मुआवजे की शेष राशि बीमाधारक से वसूल की जाएगी।

ब्याज दर- 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवज़ा देना। -अपील पर, ब्याज 9% प्रति वर्ष की दर से दुर्घटना की तारीख को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया।

न्याय निर्णय अदालत के समक्ष मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखे बिना निर्णय पर भरोसा करना उचित नहीं है - निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्णय है - अदालतों की टिप्पणियों को न तो यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही प्रावधानों के रूप में - इन टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे कहा गया है - न्यायाधीश क़ानून के शब्दों की व्याख्या करते हैं - उनके शब्दों की व्याख्या क़ानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए - निर्णय - की व्याख्या दुर्घटना में बस

के कंडक्टर की जान चली गई, उसकी विधवा, नाबालिग बच्चों और माता-पिता ने 1.40 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया। ट्रिब्यूनल ने 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 57,600/- रुपये का मुआवजा दिया। हालाँकि यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता की देनदारी 50,000/- रुपये तक सीमित थी। दावेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने मुआवज़ा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया और ट्रिब्यूनल के दायित्व के बारे में ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। हालाँकि, यह माना गया कि पूरी राशि बीमाकर्ता द्वारा दावेदारों को भुगतान की जानी थी और बीमाकर्ता वाहन के मालिक और चालक से 50,000/- रुपये से अधिक की राशि वसूल कर सकता था।

न्यायालय में अपील के दौरान अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी की देनदारी 50,000/- रुपये तक सीमित कर उच्च न्यायालय ने पूरी राशि का भुगतान करने और अंतर राशि की वसूली करना प्रतिपातिद कर न्यायालय ने उचित न्याय नहीं किया और ब्याज दर भी अधिक है।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए *अभिनिर्धारित किया*

1. यह सच है कि कुछ मामलों में इस न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति को देखने के बाद की बीमा कंपनी को बीमाधारक से दायित्व से अधिक राशि वसूल करने की स्वतंत्रता के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। वे निर्णय तथ्यों संबंधित मामलों की स्थिति पर दिए गए थे। [पैरा 10] [1146-एफ]

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सी.एम जया एवं अन्य, [2002] 2 एससीसी 278 एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शकुंतला गर्ग एवं अन्य,

(2000 की सिविल अपील संख्या 104, 10.1.2003 को निपटारा), को संदर्भित किया गया।

2.1. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखे बिना निर्णय पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कोई भी निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर एक न्याय निर्णय होता है। प्रत्येक मामलो के अपने तथ्य होते हैं। किसी न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते समय कही गई हर बात न्याय निर्णय नहीं बन जाती है [पैरा 11] [1146-जी]

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शकुंतला गर्ग और अन्य, (2000 की सिविल अपील संख्या 104 निस्तारण की 10.1.2003 उड़ीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य, एआईआर (1968) एससी 647, पर भरोसा किया गया।

2.2. एक मामला एक न्याय निर्णय है और जो स्पष्ट रूप से निर्णय लेता है उसके लिए बाध्यकारी है, इससे अधिक नहीं, न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों में प्रयुक्त शब्दों को ऐसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वे संसद के अधिनियम के शब्द हों। [पैरा 11) 1147-सी, डी]

क्विन बनाम लेदरन, (1901) एसी 495 (एच.एल.) का संधर्ब दिया गया।

2.3. न्यायालयों को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है उसकी तथ्यात्मक स्थिति किस प्रकार उक्त मामलो पर सही लागु होती हैं है। न्यायालयों की टिप्पणियों को न तो यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही क़ानून के प्रावधानों के रूप में और वह भी उनके संदर्भ से बाहर निकालक पढ़ा जाना नयोचित है। इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे कही गई प्रतीत होती हैं। न्यायालयों के निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी क़ानून के शब्दों, वाक्यांशों और

प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी करना आवश्यक हो सकता है लेकिन चर्चा का उद्देश्य व्याख्या करना है न कि परिभाषित करना। न्यायाधीश क़ानूनों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते। वे विधियों के शब्दों का अर्थ निकालते हैं उनके शब्दों की व्याख्या क़ानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

[पैरा 12) [1147-ई, एफ, जी)

2.4. परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच ज़मीन-आसमान का अंतर ला सकता है। किसी फैसले पर आंख मूंदकर भरोसा करके मामलों का निस्तारण करना उचित नहीं है। [पैरा 14) [1148-डी]

लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्टन, (1951) एसी 737; होम ऑफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी, (1970) 2 सभी ईआर 294; मेगर्री, जिन (1971) 1 डब्लूएलआर 1062 और हेरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड, (1972) 2 डब्लूएलआर 537, का उल्लेख किया गया है।

3. इस मामले में बीमाधारक परिवहन व्यवसाय करने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई जिससे यह पता चले कि दावेदारों को दी गई राशि वसूलने में कोई कठिनाई होगी। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि बीमाकर्ता दावेदारों को ब्याज के साथ 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा। शेष राशि का भुगतान बीमाधारक को करना होगा। [पैरा 16] [1149-ए, बी]

4. बीमा कंपनी का दायित्व 50,000/- रुपये तक मय आवेदन की तिथि से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ सिमित है। दर दुर्घटना की तिथि को ध्यान में रखकर तय की जा रही है।

[पैरा 17] (1149-सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 5209

1986 के आदेश संख्या 1029 प्रथम अपील चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.7.2005 अपीलकर्ता की ओर से एम.के. दुआ और किशोर रावत। प्रतिवादियों की ओर से दिनेश चंद्र यादव एवं डॉ. कैलाश चंद। श्री डॉ अरिजीत पसायत दवारा सुनाया गया ।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि अपीलकर्ता (बाद में बीमाकर्ता के रूप में संदर्भित) का दायित्व 50,000/- रुपये तक सीमित था, फिर भी उसे पहले दावेदारों को दी गई राशि का भुगतान करना था और उससे अधिक की राशि की वसूली अपराधी वाहन के मालिक और चालक से 50,000/- रु. करनी थी।

3. संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:

14.7.1984 को हुई एक दुर्घटना में बस संख्या डीईपी-3514 के कंडक्टर करण सिंह की जान चली गई। बस मेसर्स मेवात ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद बीमाधारक के रूप में संदर्भित) की थी। बस को मृतक करण सिंह चला रहा था और यह एक टैंकर संख्या एचआरजी- 2852 से टकरा गई। टक्कर इतनी तीव्र और गंभीर थी कि बस में बैठे कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

उपरोक्त करण सिंह की विधवा, नाबालिग बच्चों और माता-पिता ने 1,40,000/- रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए दावा याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने कई दावा याचिकाओं पर एक साथ विचार किया और विचाराधीन दावे के संबंध में 12% वार्षिक ब्याज के साथ 57,600/- रुपये का मुआवजा दिया। दावा याचिका संस्थित होने की तिथि से. हालाँकि, यह माना गया कि बीमाकर्ता की देनदारी 50,000/- रुपये तक सीमित थी।

4. दावेदारों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने मुआवजे के दावे को बढ़ाकर 1,25,200/- रुपये कर दिया। जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया था, यह माना गया कि बीमा पॉलिसी के संदर्भ में बीमाकर्ता की देनदारी 50,000/- रुपये तक सीमित थी। हालाँकि, यह माना गया कि पूरी राशि बीमाकर्ता द्वारा दावेदारों को भुगतान की जानी थी और वह वाहन के मालिक और चालक से 50,000/- रुपये से अधिक की राशि वसूल करने का हकदार था।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए कि बीमा कंपनी की देनदारी 50,000/- रुपये तक सीमित थी, उच्च न्यायालय द्वारा पूरी राशि का भुगतान या अंतर राशि वसूल करने का निर्देश देना उचित नहीं था।

6. उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

7. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वनाम सी.एम. जया और अन्य. (2002 (2) एससीसी 278 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने क्या कहा,

इस पर ध्यान देना उचित होगा। जया और अन्य. (2002 (2) एससीसी 278)। उस मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

"इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता, बीमा-कंपनी की देनदारी 50,000/- रुपये तक सीमित है, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने माना है। हमने जो विचार किया है, उसमें अकेले अपीलकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रति-आपत्ति की स्थिरता या मुआवजे की वृद्धि से संबंधित प्रश्न पर विचार करना अनावश्यक है, जब मालिक और ड्राइवर ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपील दायर नहीं की है।"

8. संविधान पीठ द्वारा जिन प्रश्नों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं:

"इन अपीलों में शामिल सवाल यह है कि क्या बीमा पॉलिसी के मामले में उच्च प्रीमियम स्वीकार करके कोई उच्च देनदारी नहीं ली जा रही है, किसी तीसरे पक्ष को मुआवजे के भुगतान के मामले में, बीमाकर्ता धारा 95 के तहत सीमित सीमा तक उत्तरदायी होगा (2) या बीमाकर्ता पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह अंततः बीमाधारक से वसूली कर सकता है। इस प्रश्न पर, इस न्यायालय की दो तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कुछ स्पष्ट विरोधाभास प्रतीत होता है -

(1) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शांति बाई (1995 (2) एससीसी 539) और (2) अमृत लाल सूद बनाम कौशल्या देवी थापर (1998 (3) एससीसी 744)।

2. बाद के फैसले में, दुर्भाग्य से न्यू इंडिया एश्योरेंस मामले (सुप्रा) के फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर [(1998) 1 एससीसी में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है। 626], जिस पर पहले तीन जजों की बेंच के फैसले में भरोसा किया गया था। इन दो

तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों में स्पष्ट विरोधाभास को देखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि इस मामले के रिकॉर्ड को मेरे भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है ताकि संघर्ष को हल करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सके। हम तदनुसार निर्देशित करते हैं। रिकॉर्ड अब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है।"

9. इस न्यायालय के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होगा कि तत्काल मामले में बीमा कंपनी की देनदारी उस मात्रा तक सीमित होगी जिसे पॉलिसी के संदर्भ में क्षतिपूर्ति की जानी थी। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने तदनुसार निर्णय लिया है।

10. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शकुंतला गर्ग और अन्य में। (2000 की सिविल अपील संख्या 104, 10.1.2003 को निस्तारित इस प्रकार इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया की

"इस स्तर पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आशंका व्यक्त की कि अनुदान की शर्तों के आधार पर, अपीलकर्ता को पूरी राशि का भुगतान करने और मालिक से इसकी वसूली करने की आवश्यकता हो सकती है। आक्षेपित अनुदान के संशोधन के आलोक में, ऐसा प्रश्न नहीं उठता है।"

11. यह सच है कि कुछ मामलों में इस न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति को देखने के बाद बीमा कंपनी को बीमाधारक से दायित्व से अधिक राशि वसूल करने की स्वतंत्रता के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। वे निर्णय संबंधित प्रकरणों की तथ्य स्थिति पर दिये गये।

12. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखे बिना निर्णय पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कोई भी निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर एक न्याय

निर्णय होता है। प्रत्येक न्याय निर्णय अपनी विशेषताएं प्रस्तुत करता है। किसी न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते समय कही गई हर बात एक न्याय निर्णय नहीं बन जाती। न्यायाधीश के फैसले में किसी पक्ष को बांधने वाली एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का फैसला किया जाता है और इस कारण से किसी फैसले का विश्लेषण करना और उससे अनुपात निर्णय को अलग करना महत्वपूर्ण है। उदाहरणों के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी अभिधारणाएँ होती हैं (i) भौतिक तथ्यों के प्रत्यक्ष और अनुमानात्मक। तथ्यों का अनुमानात्मक निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष, या बोधगम्य तथ्यों से निकालता है; (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों का विवरण; और (iii) उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय। एक निर्णय इस बात का प्राधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न ही उसमें पाया गया प्रत्येक अवलोकन और न ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से क्या निकलता है। कारण या सिद्धांत का प्रतिपादन, जिस पर न्यायालय के समक्ष किसी प्रश्न का निर्णय लिया गया है, एक न्याय निर्णय के रूप में बाध्यकारी है। (दे उड़ीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य। (एआईआर 1968 एससी) 647) और भारत संघ और अन्य। धनवंती देवी और अन्य। (1996 (6) एससीसी 44)। एक न्याय निर्णय एक न्याय निर्णय है और जो स्पष्ट रूप से सही तथ्य के लिए बाध्यकारी है, इससे अधिक नहीं। न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों में प्रयुक्त शब्दों को ऐसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वे संसद के अधिनियम के शब्द हों। क्विन बनाम लीथेम (1901) एसी 495 (एच.एल.) में, अर्ल ऑफ हैल्सबरी एलसी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय को सिद्ध या सिद्ध माने गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वहां पाए जाने वाले अभिव्यक्तियों की व्यापकता नहीं है

पूरे कानून की व्याख्या करने का इरादा है, लेकिन यह उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियां पाई जाती हैं और एक न्याय निर्णय केवल एक प्राधिकारी है जो यह वास्तव में निर्णय लेता है।

13. न्यायालयों को इस बात पर चर्चा किए बिना निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है उसकी तथ्यात्मक स्थिति किस प्रकार सही बैठती है। न्यायालयों की टिप्पणियों को न तो यूक्लिड के प्रमेय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही क़ानून के प्रावधानों के रूप में और ना दी उनके संदर्भ से बाहर निकाला जाकर इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे कही गई प्रतीत होती हैं। न्यायालयों के निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी क़ानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा करना आवश्यक हो सकता है लेकिन चर्चा का उद्देश्य व्याख्या करना है न कि परिभाषित करना। न्यायाधीश क़ानूनों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते। वे विधियों के शब्दों का अर्थ निकालते हैं; उनके शब्दों की व्याख्या क़ानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए। लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड वी. हॉर्टन (1951 एसी 737 पृष्ठ 761 पर) में लॉर्ड मैक डर्मोट ने कहा गया की:

बेशक, इस मामले को केवल विल्स, जे के इप्सिसिमा वर्ट्रा को इस तरह मानकर नहीं सुलझाया जा सकता जैसे कि वे संसद के एक अधिनियम का हिस्सा थे और उसके लिए उपयुक्त व्याख्या के नियमों को लागू कर रहे हों। इसका उद्देश्य उस सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश द्वारा वास्तव में इस्तेमाल की गई भाषा को दिए जाने वाले भारी महत्व को कम करना नहीं है

14. होम ऑफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी (1970 (2) ऑल ईआर 294) में लॉर्ड रीड ने कहा, लॉर्ड एटकिन्स के भाषण को ऐसे नहीं माना जाना चाहिए जैसे कि यह एक क़ानूनी परिभाषा थी। नई परिस्थितियों में इसके लिए योग्यता की आवश्यकता होगी। मेगारी, जे (1971) 1 डब्लूएलआर 1062 में कहा गया: किसी को, निश्चित रूप से, रसेल एल.जे. के एक आरक्षित निर्णय को भी इस तरह नहीं समझना चाहिए जैसे कि यह संसद का एक अधिनियम था और, हेरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड (1972 (2) डब्लूएलआर) में 537) लॉर्ड मॉरिस द्वारा कहा गया की :

"किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को ऐसे मानने में हमेशा जोखिम होता है जैसे कि वे किसी विधायी अधिनियम में शब्द हों, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की सेटिंग में किए गए हैं।"

15. परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच जमीन-आसमान का अंतर ला सकता है। किसी फैसले पर आंख मूंदकर भरोसा करके मामलों का निपटारा करना उचित नहीं है।

16. उदाहरणों को लागू करने के मामले में लॉर्ड डेनिंग के निम्नलिखित शब्द लोकस क्लासिकस बन गए हैं:

"प्रत्येक न्याय निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले और दूसरे मामले के बीच घनिष्ठ समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण विवरण पूरे पहलू को बदल सकता है, ऐसे मामलों का निर्णय लेने में, किसी को मामलों का निर्णय करने के प्रलोभन से करने से बचाना चाहिए (जेसा की कर्जोजो ने कहा था) इसलिए, यह तय करने के लिए कि कोई न्याय निर्णय लाइन के किस तरफ जाता है, दूसरे मामले से व्यापक समानता बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।

न्याय निर्णय का पालन केवल तभी तक किया जाना चाहिए जब तक यह न्याय के मार्ग को चिह्नित करता है, लेकिन आपको मृत लकड़ी को काटना होगा और किनारे की शाखाओं को छांटना होगा अन्यथा आप खुद को झाड़ियों और शाखाओं में खोया हुआ पाएंगे। मेरी दलील न्याय के मार्ग को उन बाधाओं से मुक्त रखने की है जो इसमें बाधा डाल सकती हैं।

17. वर्तमान मामले में बीमाकर्ता परिवहन व्यवसाय करने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई जिससे यह पता चले कि दावेदारों को दी गई राशि वसूलने में कोई कठिनाई होगी। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि बीमाकर्ता दावेदारों को ब्याज के साथ 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा। शेष राशि का भुगतान बीमाधारक को करना होगा।

18. अपील के समर्थन में, इस न्यायालय के समक्ष एक और मुद्दा यह उठाया गया कि ब्याज दर अधिक है। बीमा कंपनी की आवेदन की तिथि से देनदारी 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 50,000/- रुपये तक सीमित है। दर दुर्घटना की तिथि को ध्यान में रखकर तय की जा रही है। बीमाधारक को दावेदारों को ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान तुरंत करना होगा और किसी भी स्थिति में इस आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर भुगतान करना होगा।

19. शुल्क के संबंध में, बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लोचन खिड़िया देवल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।